THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

New issues vetted by SEBI

4347. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many new issues vetted by SEBI have raised capital through public issue during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 and the amount raised;

(b) how many of the issues are with premium and how many are at par during 1992-93, 1993-94 and 1994-95;

(c) how many issues with premium and how many issues at par were oversubscribed and under-subscribed during 1992-93, 1993-94 and 1994-95; and

(d) on what factors the quantum of premium fixed by Companies for their issue is based and how SEBI regulates the premium fixation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Searches conducted by IT Department in Karnataka Circle

4348. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) how many searches were conducted by the Income Tax Department in Karnataka Circle during 1992-93, 1993-94 and 1994-95; and

(b) what is the total amount of tax released from the searches during this period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) In the State of Karnataka, the details of searches conducted during financial year 1992-93, 1993-94 and 1994-95 are as under:—

Financial Year	No. of search warrants
1992-93 . . .	250
1993-94 . . .	175
1994-95 . . .	197

(b) Such data is not separately maintained. It is not feasible to do so as the search cases go through various stages of assessment, appeals etc. over a long period of time.

नाबार्ड द्वारा कराये गये सर्वेक्षण

4349. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु किसी राज्य में कोई सर्वेक्षण कराए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन एककों के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी धनराशि जुटाई जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है कि गुजरात में कृषि संस्करण क्षेत्र संबंधी संभाव्यता अध्ययन तथा विभिन्न राज्यों को शामिल करते हुए कृषि-अपशिष्टों पर आधारित पैकेजिंग सामग्री संबंधी उत्पाद अध्ययन किया गया था । गुजरात में कृषि-प्रसंस्करण के सर्वेक्षण में राज्य के 6 जिले शामिल किए गए थे और सर्वेक्षण संबंधी अन्तिम

रिपोर्ट में चुनींदा जिलों में सम्भाव्यता वाड 34 क्रियाकलापों के लिए परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु राज्य शामिल किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए पकेजिंग सामग्री के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया । इस अध्ययन में जिन अथक्षम परियोजनाओं के लिए संभाव्यता का पता लगाया गया, वे हैं जूट की छड़ियों से पार्टिकिल बोर्ड तथा जआरपी शीट्स' कपास के डंठलों से क्राफ्ट पेपर अप तथा सीएफबी बाक्स नारियल-जटा जूट की छड़ियां' कपास के डंठलों तथा अन्य कृषिजन्य अपशिष्टों का प्रयोग करते हुए, नारियल जटा (कायर) नीडल फेल्ट तथा पाली कपर बोर्ड ।

(ग) नाबार्ड ने वर्ष 1995–96 के करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता दी है। राज्यवार आबंटन निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए में)

राज्य	राशि
हिमाचल प्रदेश . .	160
जम्मू एवं कश्मीर . .	15
त्रिपुरा . . .	1
बिहार . . .	250
उडीसा . . .	10
मध्य प्रदेश . .	170
उत्तर प्रदेश . .	115
गुजरात . . .	400
गोवा . . .	8
केरल . . .	480
मिलनाडु . .	100
जोड़	1709

भारतीय बैंकों की क्षमता

4350. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु बैंकों की क्षमता में वृद्धि करने के मामले में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार हमारे बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी जारी किये जाने के संबंध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए कार्यनिष्पादन बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं से संबंधित दस्तावेजों में, बैंकों ने महत्वपूर्ण/चयनात्मक क्षेत्रों में मशीनीकरण के लिए सहमति व्यक्त की है । आशा की जाती है कि इससे विदेशी बैंकों के मुकाबले भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी ।

पिछड़े और कमजोर वर्गों को ऋण

4351. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में मिली शिकायतों की जानकारी है , जो कि गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण देने के मामले में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों को परेशान कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और